यह सब लग्जरी मुकदमे हैं, बोतलबंद पानी की क्वालिटी वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत के बड़े हिस्से में अभी भी बुनियादी पेयजल की कमी है। कोर्ट ने देश में पैकेटबंद पेयजल के मानकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इसे लग्जरी मुकदमा बताते हुए कहा कि यह शहरी भय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफी हद तक भूजल पर निर्भर हैं। देश में लोगों को बुनियादी पेयजल तक नहीं मिल पा रहा है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने याचिकाकर्ता सारंग वामन यादवाडकर से कहा गुणवत्ता का मुद्दा तो बाद में आएगा। अपनी याचिका में सारंग ने दावा किया कि भारत में बोतलबंद पानी के गुणवत्ता मानक पुराने हो चुके हैं .

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 66 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए मोदी-शाह सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया और बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि सचाई की हमेशा जीत होती है. कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी राजनीति अब बेनकाब हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'सत्यमेव जयते' में विश्वास रखती है और यह फैसला उसी का प्रमाण है.

भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोदी झूठ की आंधी, सत्य सदा है गांधी और जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़े. प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सख्ती दिखाई और देवेन्द्र यादव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से बाद में सभी को छोड़ दिया गया. इस प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, एससी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेन्द्र पाल गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार, पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डॉ. नरेन्द्र नाथ, प्रो. किरण वालिया, डॉ. योगानन्द शास्त्री समेत कई वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी शामिल रहे.

जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने प्रदर्शन को और मजबूती दी. देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती रही है. नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दर्ज किया गया केस इतना कमजोर था कि कोर्ट ने उस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया. यह बीजेपी के लिए करारा जवाब है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जिस प्रतिशोध की राजनीति की बात कर रही थी, कोर्ट के आदेश ने उसी पर मुहर लगा दी है. प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं. उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी उसी परिवार से हैं, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. देवेन्द्र यादव ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने सुनवाई इसलिए नहीं की क्योंकि यह चार्जशीट किसी मनी लॉन्ड्रिंग के वैध आधार पर नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित थी. स्पेशल जज ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में सुनवाई संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि 2014 से चले आ रहे इस मामले में न तो सीबीआई और न ही ईडी किसी को दोषी ठहरा पाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने वर्षों तक एफआईआर दर्ज नहीं की और ईडी भी लंबे समय तक ईसीआईआर दर्ज करने से बचती रही. बाद में बिना एफआईआर के ही जांच शुरू कर दी गई, जो पूरी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बनाती है. यह सब बीजेपी सरकार के दबाव में किया गया. देवेन्द्र यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह फर्जी है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत गढ़ा गया है.

बीजेपी का मिशन बंगाल ! 29 और 30 दिसंबर को राज्य का दौरा करेंगे अमित शाह

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कोलकाता में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान, वे राय भाजपा के कोर ग्रुप के नेताओं से मुलाकात करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृह मंत्री महत्वपूर्ण चुनावों से पहले पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, बूथ स्तर की योजना और पार्टी नेताओं के बीच समन्वय का आकलन करेंगे। पश्चिम बंगाल पर भाजपा के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राय में पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने के मद्देनजर यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी नादिया जिले के ताहेरपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस द्वारा राय में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के विरोध के बीच हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा फर्जी, मृत या अवैध मतदाताओं पर निर्भर हुए बिना चुनाव लड़ती है। राय में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चल रही बहस के बीच उन्होंने यह बात कही। मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि भाजपा पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास करती है और परोक्ष मतदान का सहारा नहीं लेती है। उन्होंने कहा, हम ईमानदार लोग हैं। भाजपा मृत मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निर्भर होकर चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा परोक्ष मतदान में शामिल नहीं होती है। बंगाल में मतदाता सूची में जो कुछ भी है, वह सब उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर ने उन अनियमितताओं को उजागर किया है जो वर्षों से मौजूद थीं।

हम करते हैं विविधता का सम्मान...पीएम मोदी ने ओमान से दुनिया को दिया बड़ा मैसेज

नई दिल्ली । ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते-जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं... आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारे प्रदर्शन में नजर आती है। कुछ दिनों पहले ही आर्थिक विकास के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा कि भारत की विकास दर 8व से भी अधिक रही है यानी भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। आप सभी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि ये चर्चा आपके काम आती होगी। अभिभावक हों या छात्र, सभी को तनाव मुक्त तरीके से परीक्षा देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता व्यापार से शुरू हुआ था आज उसे शिक्षा सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ओमान में

रहने वाले अन्य समुदायों के भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। आज हम एक परिवार की तरह एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में हमारी विविधता हमारी संस्कृति का एक मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम विविधता का सम्मान करते हैं। हम वहां की संस्कृति, वहां के नियम-कायदों के साथ घुल-मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं।

दिल्ली में आज से बीएस-6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश, पीयूसीसी अनिवार्य; पेट्रोल पंपों पर कतार

नई दिल्ली । जहरीली स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली में सांसत में पड़ी सांसों के बीच प्रदूषण पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज से केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के ईंधन देने पर रोक लगाने की खबर के बीच बुधवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच कराने वालों की लंबी कतार लग गई। हालांकि, तकनीकी खामियों के कारण कई पंपों पर सर्वर डाउन हो गया, जिससे जांच बाधित रही और लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हालात को संभालने के लिए पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। कई पंपों पर पीयूसी मशीनों के सर्वर डाउन होने से जांच रुक गई, घंटों इंतजार के बाद भी कई लोग निराश लौट गए। वाहन चालक नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थागत कमियां उनके सामने बड़ी चुनौती बन रही हैं। दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर कनॉट प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, जनपथ, बाराखंबा, धौला कुआं सहित कई प्रमुख पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला।

लोग सुबह से ही अपनी गाड़ियों का प्रदूषण जांच कराने पहुंचे, ताकि बृहस्पतिवार से लागू होने वाले नए नियमों का पालन कर सकें।

हालांकि, कई पंपों पर पीयूसी मशीनों के सर्वर ठप होने से जांच नहीं हो पाई। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई निराश होकर लौट गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने राजधानी के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया व बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया। बुधवार को सभी वाहनों को ईंधन भरवाने की छूट रही, लेकिन बृहस्पतिवार से सख्ती शुरू हो जाएगी। पेट्रोल पंपों पर पहुंचे वाहन चालकों ने सरकार के कदम की सराहना की, लेकिन व्यवस्थागत कमियों पर नाराजगी भी जताई। कई लोगों का कहना था कि नियम तो ठीक है।?

वाहन चालकों में दिखी नाराजगी – बाइक चालक दिव्यांश ने बताया कि पीयूसी करवाना है, लेकिन सर्वर ठप है। मैं सुबह 9 बजे से लाइन में लगा हूं। सर्वर कभी चल रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। पिछले 10 दिनों से कई पेट्रोल पंप के चक्कर काट चुका हूं। लेकिन, नए मॉडल के कारण बीएस-6 का पीयूसी नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार ने नियम बनाए हैं तो व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। वहीं, चालक विवेक ने बताया कि घर से निकलते ही पेट्रोल पंप आया हूं, लेकिन भीड़ होने के कारण पीयूसी कराने में काफी समय लग रहा है।

लोगों ने कहा कि वे प्रदूषण से राहत चाहते हैं और सरकार के फैसलों का समर्थन करते हैं, लेकिन नियमों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है। अगर पीयूसी जांच की व्यवस्था समय पर और सुचारू रूप से उपलब्ध हो। उनका कहना है कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम हमेशा प्रदूषण की मार झेलता है।

विशेषज्ञों का दावा : वाहन प्रदूषण का बड़ा स्रोत

सरकार का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कई महीनों में एक्यूआई बेहतर रहा, लेकिन नवंबर-दिसंबर में स्थिति बिगड़ी है। विशेषज्ञों का दावा है कि पीयूसी अनिवार्य करना और पुराने वाहनों पर रोक सही दिशा में कदम है। हालांकि, लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ रही हैं।

काम ठप होने पर पंजीकृत मजदूरों को ही मिलेगा मुआवजा

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए लागू सख्त पाबंदियों के बीच पंजीकृत निर्माण मजदूरों को सरकार ने जो 10 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है वह उन्हें ही मिलेगी जिनका काम ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के चलते बंद हुआ है। यह रकम सीधे उन पंजीकृत मजदूरों के खाते में जाएगी जिनका रोजगार इन पाबंदियों के कारण रुका है। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। मंत्री ने साफ किया कि यह लाभ केवल उन्हीं मजदूरों को मिलेगा, जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया अभी जारी है और मजदूरों से जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है।

प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही आप : कपिल मिश्रा

मंत्री ने विपक्षी आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री प्रदूषण के मौसम में शहर से दूर रहते थे, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रही हैं। प्रदूषण की समस्या 30 साल पुरानी है, जिसे कुछ महीनों में खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद सरकार लगातार कदम उठा रही है, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधरे और आम लोगों, मजदूरों को राहत मिल सके।

एक्यूआई देख सेंटा क्लॉज बेहोश - सौरभ

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। कनॉट प्लेस में सेंटा क्लॉज बनकर आप नेताओं ने बच्चों में टॉफी और चॉकलेट बांटी और जहरीली हवा को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्रिसमस से पहले दिल्ली आए सेंटा क्लॉज यहां की हवा देखकर बीमार पड़ गए। जब उन्हें दिल्ली का एक्यूआई दिखाया गया तो वे बेहोश हो गए। बाद में मजबूरी में उन्हें गैस मास्क पहनना पड़ा, तभी वे कनॉट प्लेस में बच्चों को टॉफी बांट पाए। आप नेता ने कहा कि सेंटा क्लॉज ने भाजपा सरकार को साफ संदेश दिया है कि अब कुछ काम करना होगा। दिल्लीवालों ने भाजपा को बहुत सोच-समझकर एक मौका दिया था, लेकिन सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।

भाजपा का पलटवार सौरभ से पूछे सवाल

प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रदूषण पर सेंटा क्लॉज वाली बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने जनपथ पर मास्क पहने एक पार्टी कार्यकर्ता को सेंटा क्लोज का रूप देकर प्रदर्शन किए जाने को ओछी राजनीति करार दिया। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने इस वर्ष क्रिसमस पर दिल्ली का प्रदूषण पहली बार बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के बारे में दिखाने की कोशिश की है, जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 ही नहीं, बल्कि 2015 से 2019 के बीच भी क्रिसमस के समय दिल्ली का प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जनता को भ्रमित करने के लिए प्रतीकात्मक और नाटकीय तरीकों का सहारा ले रही है।

प्रदूषण की मार से सूने पड़े दिल्ली के बाजार

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब कारोबार पर दिखने लगा है। प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचते ही राजधानी के बाजारों में ग्राहकों की संख्या तेजी से घट गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि हवा की गुणवत्ता खराब होने की खबरें टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर आते ही लोग बाहर निकलने से बचने लगे हैं। इसका सीधा असर दुकानों की बिक्री पर पड़ा है और बाजारों में साफ तौर पर मंदी देखी जा रही है। सीटीआई ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है।

सब का पेट भरने वाला किसान कहीं स्वयं भूखा तो नहीं?

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है। अर्थात हमारे देश का अधिकतर वर्ग किसान की श्रेणी में आता है। फिर भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, औद्योगिक वातावरण, कुशल श्रम सभी कुछ आवश्यक तत्वों के होते हुए भी आज का किसान इतना दयनीय है कि वह धीरे-धीरे किसानी जैसे जीविकोपार्जन से निराश होकर अन्य जीविकोपार्जन के लिए साधन खोजने पर विवश हो गया है। कहीं सबका पेट भरते भरते वह स्वयं ही तो भूखा नहीं रह जा रहा है यह यक्ष प्रश्न आज व्यवस्था के लिए अत्यंत विचारणीय है,और इसका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था - जय जवान जय किसान! अर्थात देश की रक्षा करने वाले सैनिक जवान हमारे लिए सम्माननीय हैं ,तो वहीं देश का पेट भरने वाले किसान भी उतने ही आदरणीय हैं। शायद उसे वक्त किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक सैनिक तो एक देश विशेष की रक्षा के लिए दूसरे देश के इंसान को मौत के घाट उतार कर अपनी देश भक्ति का परिचय देता है। वहीं एक किसान तो बिना कोई भेदभाव किया हर इंसान के लिए अन्न उपजाता है। अर्थात वह पूरे इंसानियत की सेवा करता है। इस मायने में किसान तो देवतुल्य हो जाता है। आज यह हालत है कि इस देवता की हालत ही सबसे दयनीय है। देश की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की गरीबी व पिछड़ापन। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं। इन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य का नहीं मिलना, दूसरे कृषि के उन्नत एवं सस्ते साधनों का अभाव होना, तीसरे किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध ना होना। यही तीन मुख्य कारण हैं जो हानिकारक साबित हो रहे हैं। बीच के व्यापारी- दलाल आदि इनका शोषण कर सरकार को भी आर्थिक चपत लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह सीधे किसानों से उनके उपज का विक्रय करने की व्यवस्था करें। तभी उन्हें बिचौलियों एवं व्यापारियों की बनी हुई इस गलत व्यवस्था पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। क्रय विक्रय के बीच बिचौलियों की भूमिका सर्वथा खत्म कर देनी आवश्यक है। एक बहुत बड़ी विवशता आज किसानों के साथ चल रही है। वह यह कि प्रत्येक व्यवसायी या विक्रेता को अपने विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। पर किसान को अब भी उसके उपज का विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिल पाया है। जबकि वह अपनी उपज के तैयार होने के दौरान के सभी जोखिम, प्राकृतिक विपदाओं को स्वयं अकेले के बलबूते पर ही झेलता है। परिणामस्वरूप एक किसान को उसके उपज का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता जो उसके लिए घाटे का सौदा बन जाता है। और वह पुनः इन व्यापारियों या ठेकेदारों के पास एक कर्जदार के रूप में उनका चिर ऋणी बना दिया जाता है। किसान का यह अप्रत्यक्ष शोषण न जाने कब से चला आ रहा है। इस परंपरा को अब बंद करने के लिए अब सरकारी स्तर पर कुछ ठोस पहल होना चाहिये। अगर देश का विकास करना है तो इस अधिसंख्य वर्ग के विकास के लिये सार्थक पहल उतनी ही जरूरी है, जितना अन्य व्यावसायिक कार्य। सरकारी उपक्रमों से भी किसानों को अपने कृषि कार्य के उचित संपादन के लिये खाद, बीज, ऋण, हल, बैल व अन्य साधनों को मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। हां ये भी सच है कि इन्हें यह सब प्राप्त होता है पर ऊंचे ब्याज दर के बाद और वह फिर जब अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के बाद भी ऋण को नहीं पटा पाता है तो उसके जीविका का मुख्य स्रोत खेत और खलिहान ही जप्त किया कर लिए जाते हैं। किसानों की दयनीय हालात को दूर करने के लिए कृषि का भरपूर विकास किया जाना भी अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। कृषि के विकास के लिए जरूरी है कि सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, पशुपालन, पर्याप्त खाद एवं उर्वरक तथा प्रभावी कीटनाशक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हों। किसानों का मानसिक विकास भी आवश्यक होगा। जब तक इनमें नूतनता को ग्राह्य करने की शक्ति पैदा नहीं हो जाएगी इनकी आधुनिकीकरण में रुचि नहीं होगी। कृषक को स्वावलंबी बनाने के लिए जरूरी है कि कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़े होने से बचाया जाए। यदि कृषि भूमि अपना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो फिर वह अनुपयोगी हो जाएगी। और अंतत उसे (जीविका) त्याग कर किसान मजदूरी करने या रोजी-रोटी के लिए अन्य उपाय अपनाने को बाध्य हो जाएगा। इनका पिछड़ापन दूर करने के लिए शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। साथ ही निर्बल वर्ग के अधिकारों को सरकार की ओर से संरक्षण भी जरूरी है। किसानों की प्रगति पर दृष्टि डालने से ऐसा एक भी पहलू नजर नहीं आता, जिस पर हम गर्व कर सकें।

मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद भी किसान अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पाया है। जिसका एक ही कारण है कुप्रबंधन। सक्षम प्रबंधन खराब से खराब स्थिति में भी प्रगति के द्वार खोल देता है। पंजाब व हरियाणा के किसानों की प्रगति इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुजरात व महाराष्ट्र में हुई प्रगति भी क्षमता पूर्ण प्रबंधन से ही संभव हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का उदाहरण लें, हमारे कुछ प्रदेशों की सिंचाई क्षमता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। सिंचाई के भरपूर साधनों के बावजूद हम सिंचाई के मामले में राष्ट्रीय औसत से अभी काफी पीछे हैं। इसके विपरीत जो कुछ सिंचाई क्षमता निर्मित हो पाई है, उनका भी पूरी तरह से दोहन उपयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं-कहीं तो उपयोग की क्षमता तीस या चालीस प्रतिशत से भी कम है।

यदि इस तरह की स्थिति है तो उसके लिए प्रबंधन की क्षमता ही उत्तरदाई है। किसानों को शिकायत रहती है कि बिजली, पानी, बीज, खाद आदि के लिए वे तहसील, जिला कलेक्टर और आवश्यक हो तो सचिवालय के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। इस दौरान किसानों के समय का मूल्य नहीं समझा जाता। जनशक्ति का ऐसा अपव्यय संभवत किसी स्वतंत्र देश में नहीं होता होगा। इतिहास गवाह है कि ऐसे देश का पतन अवश्य संभावित है। जनशक्ति नियोजन की प्रक्रिया उस समय तक अधूरी रहेगी ,जब तक किसानों को जायज मजदूरी और उनके समय के मूल्य को नहीं पहचाना जाएगा। वहीं कृषि के आधुनिक तौर तरीके अपनाने में भी आज का किसान पिछड़ा हुआ है इसमें अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं किए गए हैं। यदि प्रयत्न किए गए होते तो आज किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होती। हरियाणा में तो कृषि के बलबूते पर विकास की गति बढ़ी है, और इसके लाभ किसानों तक पहुंचे भी हैं। हरियाणा और पंजाब ने गत वर्षों के भीतर कृषि के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। आज वहां गन्ना ,गेहूं और बासमती धान से बाजार भरा पड़ा है। निर्धन प्रांत बंगाल तक के गांव में धान की पैदावार पहले से दुगनी कर ली गई है। अब समय आ गया है कि देखना होगा कि कृषि, सिंचाई और गरीबी की रेखा को तोड़ने के लिए कितना कुछ किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ राज्यों के कृषि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संकाय कृषकों की समृद्धि में कितना योगदान दे रहे हैं। सरकारी उपक्रम और भारी भरकम निगम राज्य और अंततः कृषकों पर बोझ तो नहीं बन गए हैं। कृषक जगत को मुक्त बाजारू प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ देने से हानि होगी या लाभ यह निश्चित ही देखना होगा। वैसे भी राजनीतिक लाभ के लिए अनैतिक रूप से लगान और सिंचाई माफी चाहे जिले को अकाल प्रस्त घोषित कर या मुफ्त अनाज देने की प्रवृत्ति अपनाकर सरकारें अनैतिकता का ही तो परिचय दे रही हैं। उसके भावी परिणाम क्या होंगे। क्या इस देश के नेतागण व सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करती हैं...? यह हम सब के सम्मुख प्रश्नचिन्ह लगाता है।

सम्पादकीय...

गरमाई सिख राजनीति

गुरु ग्रन्थ साहिब जिसे समूचा सिख पंथ जीवित गुरु के रूप में सम्मान देता है, क्योंकि सिखों के दसवें गुरु गोबिन्द सिंह जी ने देहधारी गुरु की प्रथा को समाप्त करते हुए सिख पंथ को शब्द गुरु के हवाले करते हुए ग्रन्थ साहिब को गुरु का दर्जा दिया और कहा कि आज के बाद गुरु का ग्रन्थ साहिब गुरु ग्रन्थ साहिब को जीवित गुरु के रूप में स्वीकार करेगा। आज तक अन्य धर्मों में जो ग्रन्थ लिखे गए उन्हें उनके धर्म गुरुओं के इस संसार से जाने के बाद उनके अनुयाइयों के द्वारा लिखा गया मगर गुरु ग्रन्थ साहिब एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसे गुरु साहिबान ने अपने जीवनकाल के दौरान इसकी रचना की। हर सिख को गुरु ग्रन्थ साहिब में दर्ज बाणी को पढ़कर उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए पर अफसोस कि सिख समाज केवल इसकी पूजा करने तक सिमट कर रह गया। जिन ग्रन्थी, रागी, सेवादारों की गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी बनती है वह भी बाणी को पढ़ते तो हैं पर शायद अपने जीवन में अपनाते नहीं यही वजह है कि आज सिख कौम की ऐसी दुर्दशा न हो रही होती। सिखों का युवा वर्ग लोभ लालच या फैशनपरस्ती में आकर सिखी से दूर न हो रहा होता। रही-सही कसर धर्म के ठेकेदार बन बैठे राजनेताओं ने पूरी कर दी जिन्हें गुरु ग्रन्थ साहिब की निरन्तर होती बेअदबी, बड़ी गिनती में गुरु ग्रन्थ साहिब के पावन स्वरूपों के लापता होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साल 2016 में गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों की रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला पिछले चार दशक से उलझा हुआ है जब समय पंजाब में पंथक सरकार सत्ता में थी और शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी भी उनके पास होने के बावजूद केवल खानापूर्ति करते हुए एक आध मुलाजिम पर कार्रवाई करके मामले को ठण्डा कर दिया गया, जबकि किसी मुलाजिम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह इतनी बड़ी गिनती में स्वरूपों को इधर-उधर कर सके। इसके पीछे निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिन्हें बचाने की खातिर मामला दबा दिया गया होगा। अब इससे कोई पूछे कि अगर इनका कोई पारिवारिक सदस्य लापता हो जाता तो क्या तब भी वह ऐसा ही करते या फिर इनकी नजर में गुरु ग्रन्थ साहिब मात्र एक पुस्तक की भान्ति है जिसके लापता होने से इन्हें मानो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक भी स्वरूप कोई लेकर जाता है तो बकायदा शिरोमणि कमेटी के लोग पहले उस जगह की जांच पड़ताल करते हैं जहां गुरु साहिब का प्रकाश किया जाना हो, बावजूद इसके इतने स्वरूप लापता कैसे हुए? जिन लोगों ने पावन स्वरूपों के लापता होने पर दुःख प्रकट करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की उनपर मोर्चा चलाने वाले अफसरों को पंथक सरकार ने तरक्कियां दीं इससे शर्मनाक बात कौम के लिए क्या होगी? उस समय पंजाब की कमान मरहूम प्रकाश सिंह बादल के पास थी और उनके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी आए। तीनों के शासनकाल में वह मामला केवल फाइलों में सिमटा रहा। अब जाकर भगवंत मान सरकार ने पहली बार कानूनी कार्रवाई करते हुए 16 एसजीपीसी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद समूचा सिख पंथ मान सरकार के इस कदम को न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान बल्कि पंजाब की न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरी ओर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी प्रधान इसे सिखों के धार्मिक मामलों में सरकारी दखलअंदाजी बता रहे हैं अब इनसे कोई पूछे कि 9 सालों में अगर आपने कोई योग्य कार्रवाई इस पर की होती तो सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता ही न पड़ती। गुरु के सिख का किरदार कैसा होना चाहिए? = गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना करते समय सिखों के लिए मर्यादा तय की गई थी, जिसमें पराई स्त्री को अपनी उम्र में बड़ी हो तो मां और छोटी हो तो बहन बेटी के सम्मान देकने की बात सिखाई गई थी आज तक ऐसा होता भी आया है, मगर पिछले कुछ समय से सिखों के किरदार में गिरावट देखने को मिल रही है जो कि बेहद शर्मनाक और सिखी सिद्धांतों के विपरीत है। अमरीका के स्टाकटन गुरुद्वारा साहिब के सदस्य जसपाल सिंह के द्वारा एक नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया गया जिसके चलते उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। इसी प्रकार बीते दिनों जालंधर में एक अमृतधारी सिख ने शरीर पर कृपाण धारण करने के बावजूद 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ जबरदस्ती की बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसकी वजह से समूचा सिख पंथ शर्मसार हुआ है हालांकि यह भी देखा गया कि इस घिनौनी हरकत को अन्जाम देने वाला कुछ माह पूर्व ही ईसाई से सिख बना था। बीते दिनों जब एक प्रवासी द्वारा इस तरह की घटना को अन्जाम दिया गया था तो पंजाबभर से लोगों ने सड़कों पर आकर प्रवासियों को पंजाब से बाहर करने की बात कही थी, मगर एक अमृतधारी सिख के इस करतूत ने लोगों की आवाज बंद कर दी है। सिख का किरदार तो ऐसा था कि मुगल समय में मुगलों के द्वारा जब हिन्दुओं की लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाया जाता और गजनी के बाजार में मण्डियां लगाकर बेचा जाता उस समय गुरु के सिख उन लड़कियों को छुड़वाकर पूरी हिफाजत के साथ घर तक पहुंचाते। मुगलों के साथ सिखों ने युद्ध भले ही किए मगर उनकी बहू बेटियों पर भी कभी बुरी निगाह नहीं डाली। आज तक किसी समय में भी अगर कोई सिख यह जान ले तो लोग अपनी बहू बेटियों को यह सोचकर अकेला भेज देते थे कि सिख उसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए हर माता-पिता को चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों को गुरु साहिबान और सिक्खों के इतिहास से गौरवमई इतिहास की जानकारी दें जिससे भूलकर भी कोई सिख ऐसी घिनौनी हरकत न करें, बल्कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ देखने को मिले तो अपने पूर्वजों की भान्ति अपनी जान पर खेलकर बच्चों की रक्षा करें। सिखों का तो इतिहास ही शहादतों से भरपूर है। इतिहास के पन्ने खोलते तो उसमें देखने को मिल जाएगा कि साल में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब सिखों ने अपनी शहादतें देकर देश, धर्म, मानवता की रक्षा न की हो। आज भी देश की सरहद पर आए दिन सिख सैनिकों की शहादतें होती ही रहती हैं, ऐसे में किसी भी तरह का भ्रम सिख समाज को नहीं डालना चाहिए जैसा कि इस बार देखने को मिल रहा है गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व जो कि पोह सुदी सप्तमी को आता है और इस साल उसी दिन उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत का दिन है जिसके चलते सिख समाज काफी दुविधा में था कि साहिबजादों की शहादत और गुरु महाराज का प्रकाश पर्व दोनों को एक साथ कैसे मनाया जाए? हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार भी इस पर अपना मार्गदर्शन सिख समाज को दे चुके हैं कि समाज अपनी सुविधा अनुसार प्रकाश पर्व को मना सकता है।

ममता को हराना नामुमकिन नहीं, मुश्किल तो है!

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब 4-5 महीने का समय भी नहीं बचा। अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होना है। पिछले तीन चुनावों की तरह मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखेगा, यह पक्का है। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भाजपा दस साल से तड़प रही है। मगर हर बार टी.एम.सी. नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल विजय के उसके मंसूबे पर पानी फेर देती हैं। वर्ष 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में पी.एम. मोदी के 'दीदी ओ दीदी' नारे को ममता बनर्जी ने 'खेला होबे' से पराजय रेखा के पार समेट दिया था (बांग्ला में 'व' की ध्वनि नहीं है, वहां 'ब' का ही उच्चारण किया जाता है)। हालांकि तब मीडिया के एग्जिट पोल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे थे मगर जब नतीजे आए तो कमल दल (भाजपा) 77 सीटों तक पहुंच पाया था, जबकि ममता की पार्टी ने 215 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। भाजपा ने उस चुनाव में हिन्दू-मुस्लिम कार्ड और बंगलादेशी घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया था। भाजपा को उम्मीद थी कि नागरिकता संशोधित कानून (सी.ए.ए.) का दांव चलेगा, मगर ममता ने भाजपा के इस ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह विफल कर दिया था। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी भाजपा में बड़ी सेंध लगाई गई। पाला बदलने और उपचुनावों में हार के बाद भाजपा विधायकों की संख्या सदन में और घटकर 65 ही रह गई। लेकिन अब क्या? भाजपा ने दीदी के लिए एक बार फिर से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दीदी पर पुराने आरोप, जिनमें तुष्टिकरण सबसे बड़ा है, तो लग ही रहे हैं, बंगाल की अस्मिता को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि इन आरोपों की ध्वनि को विशाल रूप देने के लिए उसके पास नेताओं का सामूहिक बिगुल नहीं है। बंगाल में भाजपा के साथ कुछ अंदरूनी दिक्कतें हैं खासकर संगठन के स्तर पर। तृणमूल पार्टी से तोड़कर लाए गए ममता दीदी के खास शुभेंदु अधिकारी को कमान देने से राज्य के पुराने भाजपाई नेता खुद को उपेक्षित मानकर अलग-अलग दिशा में चलते हैं। इनमें दिलीप घोष तो अपनी नाराजगी छुपाने की जरूरत भी नहीं समझते। पार्टी ने लंबे समय से उन्हें अपने किसी बड़े कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। चुनाव आने पर वह खुद थोड़ा सक्रिय हुए हैं। वह दीघा में ममता बनर्जी के बुलाने पर जगन्नाथ धाम के उद्घाटन समारोह में भी पहुंच गए थे। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान मचती रही है। गत जुलाई में अचानक शमीक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। शमीक के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की गुटबाजी है। पार्टी के अधिकांश नेताओं का अनुमान था कि विधानसभा चुनाव तक सुकांत मजूमदार ही अध्यक्ष रहेंगे और उन्हें इस पद से नहीं हटाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे थे। बंगाल भाजपा में पार्टी के पुराने नेताओं और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा है। शमीक गुट के नेता यह दावा करते हैं कि शमीक को अध्यक्ष बनाने से कोलकाता फैक्टर का लाभ मिलेगा। शमीक कोलकाता के ही हैं। यह बताना भी जरूरी है कि कोलकाता में भाजपा कमजोर है। इन सबके बावजूद पार्टी का केंद्रीय हाईकमान भी अब पूरी तरह से चुनाव मोड में है। इस बार कुछ नए मुद्दों के साथ बंगाल के किले की घेराबंदी की जाएगी। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की रचना के 150 साल पूरे होने पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहस का आगाज किया। वंदेमातरम गीत बंगाल की जनता के गर्व और गौरव की अनुभूति है। इसलिए संसद में इस मुद्दे पर की गई चर्चा का असर बंगाल के चुनावों में दिखेगा। भाजपा के स्थानीय नेता इसे बंगाली अस्मिता से भी जोड़ रहे हैं। दरअसल दीदी की घेराबंदी के पीछे भाजपा या दीदी की विरोधी दलों की अपनी सोच भी है। उसके नेता यह मानते रहे हैं कि दीदी को हराना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूती का राज तृणमूल कांग्रेस का पक्का और विस्तृत कैडर है। इस कैडर को सिर्फ राजनीति की डोर ही नहीं, आर्थिक संबंध भी दृढ़ता से बांधता है। राज्य में किन लोगों के काम होंगे और किनके नहीं, ज्यादातर यह कैडर ही तय करता है। विकास योजनाओं के लिए ही नहीं, आपको अपना घर बनवाना है, उसके लिए भी सारी खरीद कैडर के लोगों की तय दुकानों से होती है, यह आरोप लगते रहे हैं। नक्शे स्थानीय नेताओं के हवाले से पास होते हैं। यह भी आरोप है कि स्थानीय स्तर के सरकारी काम में भी शर्तें ऐसी ही होती हैं, जिससे कैडर को लाभ हो। आम लोगों को प्रशासन से अपना काम कराने के लिए उसी खेल से होकर गुजरना पड़ता है। दीदी के राज में कोलकाता के बड़े शहरों के बाजारों में भी यही व्यवस्था लागू है। बाजारों के कब्जे का कोई नियम नहीं है। स्थानीय नेताओं की शह पर सब चलता है, चाहे बात कोलकाता की हो या हावड़ा की, यही नियम है। इस चुनाव को धर्म के नाम पर एक बार फिर से गोलबंद करने की तैयारी चल रही है। गत रविवार को भाजपा ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ किया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ घोषणा की कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव केवल चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक 'धर्मयुद्ध' होगा। इस गीता पाठ में धीरेंद्र शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा, कार्तिक महाराज के साथ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और बड़ी संख्या में साधु-संत भी आए। इस गीता पाठ की खास बात यह रही कि लंबे समय से नाराज चल रहे दिलीप घोष ने भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का चुनावी राग छेड़ दिया है। उनकी कोशिश है कि ममता बनर्जी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का समर्थन उनसे छीनकर अपने पाले में कर लिया जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो भाजपा को लाभ मिल सकता है। इसलिए धर्मयुद्ध के नाम पर जितने भी लोग बालेंगे, वे ध्रुवीकरण का काम करेंगे। इस रणनीति से ममता बनर्जी को बड़े नुकसान का दांव चला तो दिया है, मगर यह इस पर निर्भर करता है कि बंगाल के लोग इसमें कितनी रुचि दिखाते हैं। एस.आई.आर. का मुद्दा बंगाल में दोधारी तलवार की तरह है। भाजपा जहां इसे अपने प्रतिकूल वोट काटने का औजार मान रही थी, वहीं बंगाल में उसे इस हथियार के उल्टा चल जाने का भी खतरा है।

मोदी की विदेश यात्रा

अमेरिकी टैरिफ वॉर और युद्ध के वातावरण से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जार्डन, ओमान और इथियोपिया की यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर बदल रहे समीकरणों के बीच भारत ने स्पष्ट स्टैंड लिया है कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहकर अपना मार्ग स्वयं चुनेगा। भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं आने वाला। बहुध्रुवीय विश्व में भारत नए बाजार खुद तलाश कर सकता है और अपने लिए विकल्प स्वयं चुन सकता है। तीन देशों की विदेश यात्रा ने भारत के कूटनीतिक तेवर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं। जार्डन में क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने जिस ढंग से स्वयं गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जार्डन संग्रहालय तक पहुंचाया, यह सम्मान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इथियोपिया में प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया। यह ग्लोबल साउथ के प्रति मोदी की अटूट प्रतिबद्धता और भारत-इथियोपिया दोस्ती को मजबूत करने में उनके योगदान की पहचान है। इथियोपिया का यह सर्वोच्च सम्मान मोदी को दिया गया 28वां विदेशी राजकीय पुरस्कार है। पश्चिम एशिया में जार्डन भारत का कूटनीतिक मित्र ही नहीं बल्कि व्यापार सुरक्षा का मजबूत स्तम्भ भी है। भारत और जॉर्डन के बीच 1950 से राजनयिक संबंध हैं। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन जाते समय कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में रुके थे। इसके बाद 27 फरवरी, 2018 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भारत की यात्रा की थी। कुछ सालों में जॉर्डन, भारत का सबसे अहम कारोबारी साझेदारों में से एक बनकर उभरा है। 2024-25 में दोनों के बीच 22,537 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इसमें 6,392 करोड़ का एक्सपोर्ट और 16,144 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ था। भारत की ओर से मिनरल, मिनरल ऑइल, अनाज, मांस, केमिकल, फार्मा कॉफी-चाय, मसाले और मशीनरी जैसी चीजों का एक्सपोर्ट होता है। वहीं जॉर्डन से भारत केमिकल, फर्टिलाइजर, फॉस्फेट, प्लास्टरिंग मैटेरियल और सीमेंट खरीदता है। जार्डन में केवल 167 भारतीय ही रहते हैं, जिनके पास स्थायी निवास है। वैसे वहां 17500 अप्रवासी भारतीय भी हैं।?इस बार दोनों देशों ने 5 अहम समझौते किए हैं और दोनों देशों ने 2030 तक 5 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के? खिलाफ भी भारत को जार्डन का साथ मिला है। वहीं मोदी की इथियोपिया यात्रा को देखें तो यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत निर्णायक है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय, ब्रिक्स का सदस्य और ग्लोबल साउथ की धड़कन, इथियोपिया में 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। देखा जाये तो यह देरी नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया दांव है। दोनों देशों के बीच 550 मिलियन डॉलर का व्यापार, भारतीय फार्मा की मजबूत मौजूदगी और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका दिखाती है कि नई दिल्ली अफ्रीका को बड़ा सहोदार मानती है। यह चीन के ऋण-जाल मॉडल के ठीक उलट सम्मान, प्रशिक्षण और साझा विकास का रास्ता है। भारत इथियोपिया को फार्मा, मशीनरी, लोहा, स्टील, केमिकल, प्लास्टिक का सामान, एल्युमीनियम आदि का निर्यात करता है, जबकि ओमान से हमें दालें, मसाले और चमड़ा मिलता है।

वंदे मातरम् जोड़ता है, तोड़ता नहीं

यह संतोष की बात है कि इस बार संसद चल रही है। रुकावट कम डाली गई और कई प्रभावशाली भाषण सुनने को मिले पर संसद में वंदे मातरम् को लेकर 10 घंटे की जो बहस हुई है वह मेरी समझ के बाहर है। इस महान राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इसके कवि को श्रद्धांजलि देना और आजादी की लड़ाई में इसके योगदान को याद करना अलग बात है, पर यहां तो इस गौरवमय क्षण को अपने राजनीतिक विरोधियों पर गोलीबारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि क्योंकि इस राष्ट्रीय गीत के कुछ हिस्से काट दिए गए तो यह तुष्टिकरण का मामला बन गया जिसने देश के विभाजन की नींव रख दी। भाजपा ने इसके लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराया। वंदे मातरम् को केवल दो पहले पद्यों तक सीमित रखने का निर्णय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 1937 में लिया था। तब से लेकर अब तक किसी ने इस मामले को नहीं उठाया। संसद के किसी अधिवेशन में इस पर बहस नहीं हुई। आज अचानक यह मामला इतना ज्वलंत और महत्वपूर्ण कैसे बन गया कि दिसम्बर, 2025 के संसद अधिवेशन में बाकी जरूरी मामलों की अनदेखी करते हुए इसे उठाने का फैसला लिया गया ? क्या केवल कवि और महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (चैटर्जी अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ नाम है क्योंकि वह चट्टोपाध्याय नहीं बोल सकते थे) को श्रद्धांजलि देना पर्याप्त न रहता? वंदे मातरम् वह रचना है जिसने देश की आजादी के लिए तड़प रहे देश को जागृत किया था। क्रान्तिकारियों के भी दो नारे थे, इन्कलाब जिन्दाबाद और वंदे मातरम्। यही नारे लगाते भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर झूल गए थे। बंगाल से लेकर पंजाब तक जो लहर चली थी वह अंग्रेजों के विरुद्ध सिंहनाद थी। भाषा, प्रादेशिक, धार्मिक, मजहबी, हर प्रकार के मतभेदों को पार करते हुए वंदे मातरम् गोरों के लिए एक चुनौती बन गया था। गीत बंगला और संस्कृत में है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाए थे पर वह उसका भावार्थ समझ गए थे। मातृभूमि का नमन है, वंदना है, पूजा है, गुणगान है। उस 'मां' की महिमा का वर्णन है जो जल, फल-फूल, हरी-भरी फसलें, समुद्र की ठंडी हवा, का वरदान देती है। ए.आर. रहमान द्वारा रचित गीत में भी 'मां तुझे सलाम' कहा गया है। दुःख है कि इतने सालों के बाद इसे लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है और गीत की भावना के विपरीत देश को और बांटने की कोशिश हो रही है। संक्षिप्त इतिहास कुछ उस प्रकार है - 1857 के विद्रोह के बाद लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत रोष था। 1870 में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् की कुछ पंक्तियां लिखी थीं। 1882 में उनके उपन्यास आनन्द मठ में इसका विस्तारित संस्करण शामिल किया गया। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने इस गीत का संगीत तैयार किया था और पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे खुद गाया था। इस मामले में टैगोर की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि पहले दो पद्य ही पर्याप्त हैं। यह असामान्य नहीं है। कई देशों के राष्ट्रीय गान छोटे किए गए हैं।

राष्ट्रीय गान जन गण मन भी रवीन्द्र नाथ टैगोर की पूरी कविता का हिस्सा है। कुछ मुसलमानों द्वारा पूरे गीत में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के वर्णन पर आपत्ति की गई थी, क्योंकि उनके अनुसार देवी की स्तुति उनकी धार्मिक भावना को आहत करती है। उस वक्त नेताजी सुभाष बोस ने नेहरू को पत्र लिखा था कि कांग्रेस कार्यकारिणी में इस पर बहस होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का जवाब था कि ÷वंदे भारत का विरोध फिरकापरस्तों द्वारा किया जा रहा है÷ हमें साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर जहां सही शिकायतें हैं उनका निवारण होना चाहिए÷। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने भी सरदार पटेल को पत्र लिखा था कि उन्हें आशंका है कि इस गीत का भारी विरोध होगा और इस पर बहस होनी चाहिए। तब दोनों जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस ने टैगोर को पत्र लिखकर पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? टैगोर का नेहरू को जवाब था, ÷मैं पूरी तरह से यह स्वीकार करता हूं कि पूरी वंदे मातरम् कविता÷ मुसलमानों की भावना को आघात पहुंचा सकती है÷। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि पहले दो पद्य ही राष्ट्रीय गीत के लिए पर्याप्त हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है कि इसके बाद वंदे मातरम् को उस रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1939 में गांधी जी ने लिखा, आपत्ति को देखते हुए कांग्रेस ने वही पद्य रखे हैं जिन पर कोई आपत्ति न हो सके÷। स्पष्ट है कि जिस समय देश आजादी की बड़ी लड़ाई में लगा हुआ था नेतृत्व नहीं चाहता कि वंदे मातरम् को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जिससे लड़ाई कमजोर पड़ जाए। गांधी जी ने फिर अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा था कि वह ÷वंदे मातरम् को लेकर एक भी झगड़े का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। मुहम्मद अली जिन्ना ने तो पहले दो पद्यों का भी विरोध किया था। 1938 में उसने नेहरू को लिखा था कि चारों तरफ मुसलमानों ने वंदे मातरम् या इसके मुस्लिम विरोधी गीत के संक्षिप्त संस्करण को राष्ट्रीय गीत स्वीकार करने से इंकार कर दिया है÷। संविधान सभा में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि जन गण मन और वंदे मातरम् दोनों का बराबर का दर्जा होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी फैसला लिया गया वह सब नेताओं, गांधी जी, टैगोर, नेहरू, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष बोस ने मिलकर लिया था। आज भी वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है पर अधिकतर पहले दो पद्य ही गाए जाते हैं, पर जैसा आजकल आम होता है, यह राष्ट्रीय गीत भी विवाद का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए एक बार फिर सारा दोष नेहरू के सर पर मढ़ दिया है। उनका कहना था कि नेहरू मुस्लिम लीग के दबाव में आ गए और वंदे मातरम् से विश्वासघात किया गया। यह निर्णय जैसे हम ऊपर देखकर हटे हैं, सामूहिक था। केवल नेहरू पर निशाना लगाना जायज नहीं है। वैसे भी उस समय के नेतृत्व ने क्या निर्णय लिए, क्या नहीं, उसे आज की परिस्थिति से तोलना भी सही नहीं है। उन्होंने देश को आजादी लेकर दी। जेल गए। यातनाएं झेलीं। संघर्ष किया। उनका सम्मान होना चाहिए। जो भी बड़े निर्णय लिए गए उनमें सभी बड़े नेता शामिल थे, वह केवल नेहरू के नहीं थे। सरदार पटेल ने भी देश के बंटवारे को ÷अप्रिय लेकिन अपरिहार्य÷कहा था पर दोष केवल नेहरू पर मढ़ा जा रहा है। नेहरू ने 9-10 साल जेल काटी थी। सरदार पटेल ने लिखा था कि किसी ने भी आजादी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पर आज उनकी अनावश्यक आलोचना हो रही है। भारत आज जो है उसकी नींव जिन लोगों ने रखी उन में नेहरू प्रमुख थे। वैसे भी हमारी तो संस्कृति है कि जिसका देहांत हो गया उसकी अवमानना नहीं करते। संसद में अपने प्रभावशाली भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि नेहरू जी को जो गालियां निकालनी हैं एक बार निकाल लो, फिर बस करो और जनता के मुद्दों पर बहस करो। यही बात सारा देश भी कह रहा है। संसद ने दस घंटे वंदे मातरम् पर बहस की पर क्या इससे आम आदमी के जीवन में कोई सुधार हुआ? लोग तो हैरान हैं कि 150 वर्ष बाद वंदे मातरम् विवादास्पद कैसे बन गया? किसी भी क्षेत्र से इस पर बहस की मांग नहीं उठी थी। संसद में जो बोल रहे थे, कुछ तो कवि का पूरा नाम भी नहीं जानते थे और कितने हैं जो पूरा वंदे मातरम् गा सकते हैं? पर उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा है। जनजीवन अस्त-व्यस्त है। हमारी राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। महंगाई की समस्या है। शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है। बेरोजगारी से जूझना है। सारे देश में क्राइम बढ़ रहा है। इन सब पर गम्भीर बहस की जरूरत है। इंडिगो का संकट बताता है कि हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का भट्ठा बैठ गया है। कोई जिम्मेवार नहीं? लोग अपनी संसद पर बहुत आशा लगाकर बैठे हैं पर संसद वर्तमान की चिन्ता करने की जगह पीछे की तरफ देख रही है। वंदे मातरम् के 150 साल जश्न मनाने का अवसर है, अनावश्यक विवाद खड़े करने का नहीं। न केवल उसके शब्दों का, बल्कि उसकी भावना का भी जश्न होना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल जोड़ने के लिए होना चाहिए तोड़ने के लिए नहीं। इस देश में विवाद खड़ा करना बहुत आसान है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/00882)

हिजाब पर बिहार के सीएम का ब्यान धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफः मुफ्ती दानिश

मुरादाबाद।

मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत, मुरादाबाद के नायब सदर मुफ्ती दानिश क़ादरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री द्वारा हिजाब को लेकर दिए गए हालिया बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर इस तरह के बयान न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, बल्कि समाज में नफरत और तनाव को भी बढ़ाते हैं। मुफ्ती दानिश क़ादरी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी देता है और किसी भी धार्मिक पहचान को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्दा और शालीनता की परंपरा केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसकी मान्यता रही है, जहां घूंघट को सम्मान और मर्यादा की निशानी माना जाता है। ऐसे में हिजाब पर आपत्तिजनक टिप्पणी दरअसल साझा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयानों से एक विशेष समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं और आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। मुफ्ती दानिश क़ादरी ने मांग की कि संबंधित नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से पहले सोचे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अंत में उन्होंने सरकारों से अपील की कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से बचें, संविधान की मर्यादा का पालन करें और देश के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं।

वन्दे मातरम् का मसलाः हिन्दू धर्म और कल्चर को ज़बरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिशः कौसर हयात

मुरादाबाद।

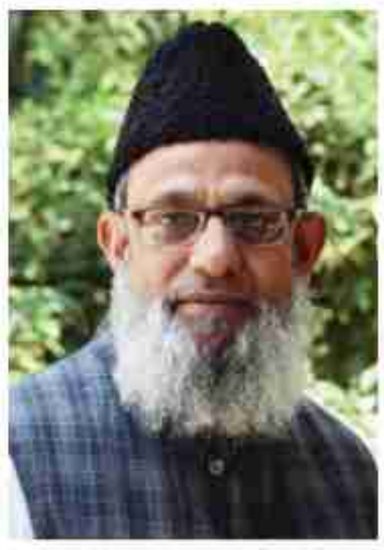

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता कौसर हयात खान का कहना है कि अब तक देश के अराजक और शरारती तत्वों ने जिस तरह से वंदे मातरम और जय श्री राम के खिलाफ हिंसा की है, उसका सभी गंभीर लोगों ने खुलकर विरोध किया है। और देश के लोगों को यह मैसेज गया है कि ये काम सिर्फ कुछ गलत तत्वों ने किए हैं। जो कि निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट का एक सेशन सिर्फ वंदे मातरम के लिए रिज़र्व किया है और जिस तरह से वंदे मातरम का मुद्दा देश के सामने रखा है, उससे पता चलता है कि आज की सरकार और रूलिंग पार्टी को इस देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं की कोई इ'ज़त नहीं करती है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों पर हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर थोपने की साज़िश रची जा रही है। जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल धर्म है और इसका एक मुकम्मल कल्चर है। और इसका एक ग्लोबल स्टेटस है। इस्लामिक धर्म और इस्लामिक कल्चर देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है और न ही बदलता है। चाहे कोई देश यहूदियों का हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का हो या हिंदुओं का। एक मुसलमान हर हाल में इस्लामिक धर्म और कल्चर से बंधा होता है। इसके अलावा, इस देश का एक संविधान है। भारत का संविधान देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे सभी धर्मों को मानने वालों के बीच एक प्रस्ताव और समझौता है। इस समझौते में देश के हर एक रहने वाले की धार्मिक मान्यताओं को सम्मान दिया गया है और उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी गई है। इसके बाद भी अगर मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी थोपने की कोशिश की जाती है, तो यह भारत के संविधान का साफ उल्लंघन है। और यह मुसलमानों को मंजूर नहीं है। इसलिए, देश के बड़े हित में, सरकार से अपील है कि वह देश में रहने वाले सभी धर्मों के मानने वालों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करे और ऐसा कोई भी कदम न उठाए जो साफ तौर पर भारत के संविधान के खिलाफ हो।

वार्डन्स को अग्नि त्रिकोण और दहन के सिद्धांत की दी जानकारी

मुरादाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा उ. प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र के दूसरे दिन प्रशिक्षण से पूर्व नीरज चक, उपनियंत्रक के साथ सभी उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों ने 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना गायी । सतीश कुमार सहायक उपनियंत्रक (व. वे.) द्वारा पहले सेशन में अग्नि त्रिकोण और दहन के सिद्धांत के बारे में बताया गया। दूसरे सेशन में नीरज चक, उपनियंत्रक द्वारा आग बुझाने की विधि एवं उपकरणों के बारे समझाया गया। दूसरे दिन के अंतिम सेशन में सतीश कुमार सहायक उपनियंत्रक द्वारा आग का वर्गीकरण, लगने के कारण एवं बचाव पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त विवेक यादव एवं अखिल अग्रवाल मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय से चमन कुमार शर्मा, तुषार अग्रवाल डिविजन वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, मो0 खालिद, स्टाफ अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, वसीम अख्तर आदि ने उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया।

वेस्ट नहीं, वेल्थ है: जब सोच बदलती है, तो कचरा भी बनता है कला

मुरादाबाद।

प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में एस.के. मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल, हरथला में वेस्ट टू आर्ट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस रचनात्मक प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, सृजनशीलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने घरेलू अपशिष्ट, अनुपयोगी एवं फेंकी जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग कर सुंदर, आकर्षक तथा उपयोगी कलाकृतियों का निर्माण किया। इन कलाकृतियों में ब'चों की कल्पनाशील सोच, रचनात्मक प्रतिभा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या आकांक्षा भटनागर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे यह समझते हैं कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि यदि कचरे का सही उपयोग किया जाए तो न केवल पर्यावरण संरक्षण संभव है, बल्कि कचरा प्रबंधन जैसी गंभीर समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है। समिति के संस्थापक एवं महासचिव पर्यावरण सचेतक नैपाल सिंह पाल ने कहा कि ब'चों की रचनात्मक सोच हमें यह संदेश देती है कि बेकार समझी जाने वाली वस्तुएँ भी उपयोगी और मूल्यवान बन सकती हैं। ऐसे कार्यक्रम स्व'छता, पुनर्चक्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समाज को प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतियोगिता के विजेता अनुज प्रथम , लविका द्वितीय , रचित तृतीय , शुभी और दिव्यांशी को सांत्वना रूप से रहे। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या आकांक्षा भटनागर , प्रीति भटनागर ,शिवानी , अंजू ,प्रीति यादव , कशिश , अनामिका, रूपाली समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतिभागी छात्र छात्राओ में मयंक ,देवदूत,जुबैर ,वंश ,आराधना,मयंक,शिवम ,शिव ,अंकुश ,लोकेश ,डेविड ,कृष्ण , अवनि ,दीपांशी शिका ,दीपक ,वृद्धि भटनागर , खुशी आदि प्रतिभागी रहें।

कूड़े-कचरे के सही प्रबन्धन के बताये तरीके

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद द्वारा आज भारतीय बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद के अतुल चौहान, अंजनी शुक्ला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण मित्र समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने की।

कार्यशाला में अतुल चौहान ने सभी छात्र छात्राओं को अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर पूरी जानकारी दी तथा घर, विद्यालय अथवा समाज में कैसे कूड़े कचरे का प्रबंधन किया जाए इस बात की जानकारी दी। इस अवसर पर कुछ ब'चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी तथा कुछ बच्चों ने भाषण एवं चित्रों के माध्यम से विशेष प्रस्तुति दी।

बच्चों में निधि, पलक, 'योति, अर्चना, मुस्कान, निशि, संजना, गुड़िया, वैशाली, मेघा, खुशी, खुशबू, अंशिका को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन के के गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सहयोगी शिक्षिकाएं रीना सिंह, मधु भटनागर, मोनिका बजाज, 'योत्सना जी, अजय शर्मा, स्वप्निल मिश्रा जी का विशेष सहयोग हेतु सम्मान किया गया। आभार अभिव्यक्ति विद्यालय प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने की। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

सिनेमाघरों का होगा उच्चीकरण, सरकार ने शुरू की प्रोत्साहन योजना

एडीएम वित्त ने दी जानकारी

मुरादाबाद। नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय ने बताया कि जिले में बंद पड़े एवं चालू सिनेमाघरोंके स्वामी/लाइसेंसी/ प्रबंधक अथवा संचालक या अन्य इच्छुक व्यक्ति/ फर्म या कंपनी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सिनेमाघर जो बंद पड़े हैं अथवा घाटे में चल रहे हैं उनको पूर्ण रूप से तोड़कर उनके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमा हॉल सहित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, पुराने बंद पड़े अथवा सचालित सिनेमाघरों के भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघर, बंद पड़े एकल सिनेमाघरों में बिना किसी आंतरिक संरचना में परिवर्तन किए यथास्थिति में पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघर, व्यवसायिक गतिविधियों सहित अथवा रहित न्यूनतम 75 आसान क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण एवं सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स का उच्चीकरण हेतु यह योजना संचालित है। शासन स्तर से जारी इस संबंध में दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी या अन्य सहयोग एवं सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर (पूर्व में मनोरंजन कर विभाग) कलेक्ट्रेट परिसर मुरादाबाद में संपर्क किया जा सकता है।

भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने घेरा

फतेहपुर।

नारेबाजी करते हुए कहा-राहुल व सोनिया से माफी मांगे मोदी

सोनिया गांधी व राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेरॉल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाली ई डी की चार्जशीट को कोर्ट द्वारा संज्ञान न लेने व उसे द्वेषपूर्ण कार्यवाही बताने पर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जिला भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। जहां पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने कांग्रेसियों को भाजपा कार्यालय के बाहर ही घेरकर रोक दिया। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की कि राहुल व सोनिया से मोदी माफी मांगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा जबरन गरीब व ग्रामीण योजनाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस द्वारा लागू की गई मनरेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग की मेहनत के बदले उचित पारिश्रमिक देकर उनका जीवन यापन सुधारना था उसे गोडसे राम जी के नाम से चालू कर धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इन जनविरोधी नीतियों को कांग्रेसी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि आज जनता के सामने ई डी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, सरकार की सह पर जबरन कांग्रेस नेताओं को फंसाया गया। तमाम नेताओं को डरा कर कांग्रेस छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, परन्तु सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले कांग्रेसी हर मोड़ पर संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी को राहुल गांधी व सोनिया से माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से इस केस में दोनों नेताओं को प्रताड़ित किया गया बहुत ही शर्मनाक है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से, संतोष कुमारी शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, कलीम उल्ला सिद्दीकी, शिवाकांत तिवारी, देवी प्रकाश दुबे, उदित अवस्थी, पंडित राम नरेश महराज, ओम प्रकाश कोरी, अनुराग नारायण मिश्र एडवोकेट, आदित्य श्रीवास्तव एडवोकेट, चौधरी मोइन राईन, सैयद शहाब अली, राजेन्द्र लोधी उर्फ राजू, राजन तिवारी, मनोज गुप्ता घायल, सरदार नरेन्द्र सिंह रिंकी, शकीला बानो, अजय बच्चा, कौशल कुमार शुक्ला, कल्लू कोरी, मो0 अकरम काले, राम चरण पासवान, आनंद सिंह गौतम, बसीर अहमद, मो0 इस्माइल, मो0 असलम, इंद्र जीत लोधी, नवनीत तिवारी, शमशाद अहमद, शैलेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, लाल तिवारी आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के नेता ने की नई परंपरा की शुरुआत

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सदन के नेता के रूप में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी एवं अभिनंदन किया, जो हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता चुने जाने पर सदन के नेता द्वारा नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया गया हो। मुख्यमंत्री की इस पहल का श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्वागत किया और कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते है, लेकिन मनभेद नहीं। लोकहित में मनभेद नहीं होने चाहिए। विपक्ष की ओर से हम केवल राजनीतिक मतभेद तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे और यही आशा सत्ता पक्ष से भी है, इस तरह हम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर किया स्वागत

जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष

के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि 15वीं विधानसभा को विपक्ष के नेता के रूप में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता मिले है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा नाम है, जो राजनीतिक अनुभव, विधायी कार्यों की गंभीरता और महन प्रशासनिक समझ के प्रतीक माने जाते है। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा व संसद तक, हर मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी विश्वास के बलबूते वे 4 बार लोकसभा तथा 6 बार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस महान सदन के नेता भी रहे है। उनका संसदीय अनुभव, प्रक्रियाओं की गहरी समझ और विषयों पर उनका मजबूत पकड़, सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाता है। वह सुझाव देता है और जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी नेता का इस पद पर होना निश्चित रूप से इस सदन की कार्यवाही को अधिक सार्थक, गंभीर और रचनात्मक बनाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज विकास के एक नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता ने हमें 'नॉन स्टॉप' सेवा और सुशासन की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में सरकार और विपक्ष, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अनुभव और ऊर्जा मिलकर काम करें, तो जनहित के बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते है।

हंगामे के बीच वीबी-जी राम जी बिल लोकसभा से पास

विपक्ष ने कागज फाड़े; शिवराज बोले- चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम

नई दिल्ली।

संसद के हंगामेदार सत्र में, लोकसभा ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने तीखे विरोध प्रदर्शन किए और सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा में कहा कि अपनी बात कहना है और फिर जवाब नहीं सुनना भी 'हिंसा' है, विपक्ष के लोग बापू के आदर्शों के खिलाफ काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मनरेगा के नाम ढोंग करते है, मोदी सरकार काम करती है। चौहान ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम रखने की सनक कांग्रेस की है, बहुत सारी योजनाओं के नाम नेहरू परिवार को महिमामंडित करने के लिए रखे गए। शिवराज ने कहा कि यह आवश्यक हो गया था कि मनरेगा के पैसे का सही उपयोग हो, लूट बंद हो, पारदर्शिता हो,

शिवराज बोले- कांग्रेस ने बापू के आदर्शों का किया नाश, हम भेदभाव नहीं करते

इसलिए इस योजना पर खुले मन से विचार किया गया और नई योजना लाने का फैसला हुआ।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव जरूरी है, यही इस योजना का उद्देश्य है। चौहान ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि शुरुआत में यह एनआरईजीए था और विधेयक में महात्मा गांधी का नाम शामिल नहीं था। बाद में, जब 2009 के आम चुनाव आए, तो कांग्रेस ने वोट पाने के लिए बापू गांधी का नाम याद किया। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजीएनआरईजीए को सही ढंग से और मजबूती से लागू किया। जीआरएएम जी विधेयक पर आठ घंटे चली चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अपने द्वारा की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से महात्मा गांधी के आदर्शों को बरकरार रखने को सुनिश्चित कर रही है। चौहान ने कहा, कांग्रेस ने बापू के आदर्शों का नाश किया, एनडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत के तहत बने पक्के मकानों के जरिए बापू के जीवन को संजोया। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की इस आलोचना का भी खंडन किया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदलती है और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नाम पर रखे गए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का उदाहरण दिया।

भारत-ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील समझौते पर हुए हस्ताक्षर

पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला, सुल्तान हैथम ने सम्मानित किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (18 दिसंबर 2025) को ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान भारत और ओमान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर ओमान सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया. इस समझौते से भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इससे रोजगार सृजन होगा और कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के साथ-साथ स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी. यह पिछले छह महीनों में भारत का दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. भारत ने पिछले कुछ सालों में कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को लाभ मिल रहा है. भारत का पहले से ही खाड़ी सहयोग परिषद के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसी तरह का समझौता है, जो मई 2022 में लागू हुआ था. जीसीसी के अन्य सदस्य बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर हैं. भारत और कतर भी जल्द ही व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था. केंद्रीय पीयूष गोयल ने बताया कि भारत-ओमान फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, एग्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स में नए अवसर पैदा होंगे. भारत-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में ओमान को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बताया, जो भारतीय व्यवसायों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है.

विपक्ष का संसद परिसर में विरोध मार्च, खरगे बोले- इस बिल के खिलाफ हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे

नई दिल्ली। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर के अंदर जी-राम जी विधेयक के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इसे वापस लेने की मांग की। महात्मा गांधी एनआरईजीए के विशाल बैनर के पीछे, वह प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद और सड़कों पर सरकार के इस कदम का विरोध करने का संकल्प लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, डीएमके की के कनिमोझी, टीआर बालू, ए राजा, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन सहित अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

मोदी सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही - खरगे

विरोध प्रदर्शन के बाद खरगे ने एक्स पर पोस्ट कहा, मोदी सरकार ने न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है, बल्कि काम करने के अधिकार को भी कुचल दिया है, जो भारत के गांवों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके साथ ही खरगे ने कहा, सत्ताधारी तानाशाही सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ हम संसद से लेकर सड़कों तक लड़ेंगे। वहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ मकर द्वार पर हुए प्रदर्शनों में शामिल हुईं।

आज संसद में लोकतंत्र की हत्या हो गई - वेणुगोपाल

पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, आज संसद में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एनआरईजीए से महात्मा गांधी का नाम हटाकर वे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ राष्ट्रपिता की विचारधारा को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे है। यूपीए सरकार के शासनकाल के एमजीएनआरईजीए की जगह लेने के लिए विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) विधेयक पर संसद में बहस चल रही है। विपक्ष इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है और सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। इस विधेयक के अनुसार, यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है। वीबी-जी रैम जी अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर, राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप एक योजना बनानी होगी।

मनरेगा कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, जी-राम-जी बिल पर बोलीं प्रियंका, यह गरीबों के खिलाफ

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में पारित वीबी-जी-राम-जी विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक एमजीएनआरईजीए के भविष्य के लिए खतरा है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। इस विधेयक के साथ एमजीएनआरईजीए आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही राज्यों पर बोझ पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। यह विधेयक गरीबों के खिलाफ है। प्रियंका ने आगे चिंता व्यक्त की कि विधेयक के लागू होने से राज्य सरकारों पर अनावश्यक जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली इस कल्याणकारी योजना को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आप इसे किसी भी तरह से देखें, और कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझ जाएगा, यह 100 से 125 दिनों की एक चालाकी भरी चाल है। अगर कोई इस विधेयक को पढ़ेगा, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि यह पूरी योजना आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही इतनी बड़ी रकम मुहैया कराने का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक को बिना सहमति के पारित कराया गया। जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, उससे साफ है कि भाजपा के लोग और यह सरकार बापू से नफरत करती है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बेकार हो जाएगी। द्रमुक सांसद कनिमोझि करुणानिधि ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से ग्रामीण भारत के खिलाफ है और अब केंद्र सरकार यह निर्णय लेगी कि किन लोगों और किन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना शर्मनाक है।

श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी; तीन की मौत और पांच घायल

भवाली। पीलीभीत से कैंची धाम दर्शन के लिए जा रही सैलानियों से भरी स्कॉर्पियो भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में निगलाट के करीब अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में तीन सैलानियों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर खाई से निकालकर भवाली सीएचसी ले जाया गया। कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि हादसे में त्रंबि पटेल (7) पुत्र राहुल पटेल निवासी बरेली एयरपोर्ट एयरफोर्स पीलीभीत रोड, इज्जतनगर, स्वाति (20) पुत्री भूपराम, अक्षय (20) पुत्र नंदन सिंह पटेल, योति (25) पत्नी करन निवासी, करन (25) पुत्र जितेंद्र, राहुल पटेल (35) पुत्र भूपराम, गंगा देवी (56) पत्नी भूपराम, बृजेश कुमारी (26) पुत्री राहुल पटेल और नैंसी गंगवार (24) पुत्री जयपाल सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया।

ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा - राज्य में गांधी के नाम पर रखेंगे रोजगार योजना का नाम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी राम योजना करने के कदम को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार अपने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेगी। बनर्जी ने यहां आयोजित एक व्यापार और उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल ''हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करने में विफल रहते है, तो यह हम करेंगे।'' हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा का नाम नहीं लिया। बनर्जी की ओर से यह घोषणा ऐसे समय आयी जब लोकसभा ने 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पारित कर दिया जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा। बनर्जी ने धन धान्य सभागार में आयोजित कारोबारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे शर्म महसूस होती है कि उन्होंने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं भी इसी देश की हूं। अब हम राष्ट्रपिता तक को भूला रहे है।'' उन्होंने कहा, ''अब हम अपने राज्य की 'कर्मश्री' योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे।'' 'कर्मश्री' योजना के तहत राज्य सरकार का दावा है कि लाभार्थियों को 75 दिनों तक काम उपलब्ध कराया जाता है, जबकि बनर्जी के अनुसार केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत धनराशि रोक रखी है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य भविष्य में 'कर्मश्री' योजना के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का है। उन्होंने कहा, ''हमने 'कर्मश्री' के तहत पहले ही अपने संसाधनों से कई कार्यदिवस सृजित किए है। भले ही केंद्र की निधि रोक दी जाए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को काम मिले। हम भिखारी नहीं है।

कोडीन-युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचा रही भाजपा : अखिलेश

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करोड़ों रुपये के कोडीन-युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया। यादव ने सपा विधायकों की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कथित कोडीन और कफ सिरप रैकेट एक बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने आरोप लगाया, कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर चिंता सिर्फ उत्तर प्रदेश के आम लोगों तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। यह रैकेट एक प्रधान सांसद (वाराणसी) के इलाके से शुरू हुआ और इसके तार न सिर्फ पूरे देश बल्कि विदेशों तक फैले हुए है। यादव ने दावा किया कि जो शुरू में कुछ करोड़ रुपये का घोटाला लग रहा था, वह अब हजारों करोड़ रुपये का रैकेट बनकर सामने आ रहा है, जिसके मुख्य तार सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिलों से जुड़े है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा रैकेट उत्तर प्रदेश से चलाया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन और 'मनी ट्रेल की जांच की जा रही है और प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है।

खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोडीन युक्त सिरप 'शेड्यूल एच के तहत आता है और ये सिर्फ चिकित्सक के पर्चे पर लिखे होने के बाद ही बेचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि लेकिन जब बड़ी मात्रा में बिना कागजों के इसकी आपूर्ति की जाती है तो ये कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों ने बताया कि इसका इस्तेमाल अक्सर नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 28 जिलों में 128 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कानून प्रवर्तन दृष्टिकोण पर निशाना साधते हुए कहा कि उच्च स्तरीय मामलों में आमतौर पर बुलडोजर तेजी से तैनात किए जाते हैं लेकिन इस मामले में कार्रवाई गायब दिख रही है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार के बुलडोजर का चालक भाग गया है और चाबी खो गई है। यादव ने चयनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य भर में 22 बड़ी बुलडोजर कार्रवाई में लक्षित लोगों में से अधिकांश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्गों के थे। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सिरप मामले की जांच के लिए बनाई गई एसटीएफ टीमों में एक ही जिले के कर्मियों का दबदबा था और वे समझौता कर चुके थे। यादव ने अधिकारियों पर दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची से मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम काटने के निर्देश दिए जा रहे है। उन्होंने इस काम को 'एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) करार दिया और दावा किया कि यह निर्वाचन आयोग के जरिए किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया।

आवारा कुत्ते मामले में अदालत सख्त, याचिकाकर्ता से कहा- हम वीडियो चलाकर पूछेंगे मानवता क्या है?

नई दिल्ली। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को अमानवीय बताने वाली आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो चलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि मानवता आखिर है क्या। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो इस मामले में पक्ष रख रहे है, ने बताया कि इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गुरुवार को गठित होने वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ की बैठक रद्द कर दी गई है। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला 7 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि समस्या यह है कि इस बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कुछ ऐसे नियम बना दिए है जो पूरी तरह से विपरीत है। जब पीठ ने कहा कि वह 7 जनवरी को इस मामले पर विचार करेगी, तो सिब्बल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू कर देंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों को हटा देंगे। उनके पास आश्रय स्थल नहीं है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। सिब्बल ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों के पास कुत्तों के लिए आश्रय स्थल तक नहीं है। उन्होंने कहा, जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद अमानवीय है। न्यायमूर्ति मेहता ने सिब्बल से कहा कि अगली तारीख को हम आपके हित में एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है। सिब्बल ने जवाब दिया कि वे यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी चलाएंगे कि क्या हो रहा था। सिब्बल ने कहा, समस्या यह है कि आपके माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है और हम उसका सम्मान करते है। लेकिन मुद्दा यह है कि वैधानिक नियम है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 7 जनवरी को विचार करेगी। बता दें कि 7 नवंबर को, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को तुरंत निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने यह भी कहा था कि इस प्रकार पकड़े गए आवारा कुत्तों को उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पीठ ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि खेल परिसरों सहित संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित करने में प्रणालीगत विफलता को भी दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले में कई निर्देश जारी किए थे। यह राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने, विशेष रूप से बच्चों में, की घटना पर मीडिया रिपोर्ट के संबंध में 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है।